

नागरिक विविध

डी. के. महाजन और, ए. डी. कोशल से पहले, जे.जे.

एमएस। मामन चंद कुन्दन लाल,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1969 की सिविल रिट संख्या 109

17 दिसंबर 1969

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1948 का XLVI)-धारा 6 और अनुसूची 'बी', आइटम 15 और 54-'ग्राम चिल्का'-चाहे आइटम 15 और 54 के तहत आता है और बिक्री कर से मुक्त है-भारत का संविधान (1950)-अनुच्छेद 226 और 227-कानून के अधिकार के बिना लगाया गया कर-अपील और संशोधन का वैकल्पिक उपाय रखने वाले करदाता- क्या उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है।

माना जाता है कि 'ग्राम चिल्का' चने के बीज से निकाली गई भूरे रंग की त्वचा के अलावा और कुछ नहीं है और 'ग्राम भूसी' शब्दों के लोकप्रिय और शब्दकोश अर्थ के भीतर आता है। चने की भूसी के रूप में जानी जाने वाली वस्तु को वाणिज्यिक दुनिया में चने के बीज की भूरे रंग की त्वचा के रूप में समझा जाता है, न कि चने की भूसी जो झाड़ने की प्रक्रिया के दौरान पूरे चने से अलग हो जाती है। शब्दकोश के अनुसार चने की भूसी में न केवल 'चने का छिलका' होता है, बल्कि चने की भूसी के साथ-साथ चने की फली भी होती है। इसलिए, शब्दकोश का अर्थ चने की भूसी के रूप में जानी जाने वाली वस्तु से जुड़े लोकप्रिय अर्थ से अधिक व्यापक है। यदि शब्दकोश के अर्थ को पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की अनुसूची 'बी' की मद 15 के प्रयोजनों के लिए अपनाया जाता है, तो न केवल ग्राम चिल्का बल्कि ए. जे. एस. ओ ग्राम चफ उस मद के अंतर्गत आएगा और इसलिए ग्राम चिल्का किसी भी मामले में बिक्री कर से छूट के लिए उत्तरदायी होगा।

माना जाता है कि वह ग्राम चिल्का भी अधिनियम की अनुसूची 'बी' की मद 54 के दायरे में आता है। चना चिल्का का मुख्य उपयोग मवेशियों के भोजन के रूप में और इसलिए चारे के रूप में किया जाता है। यह मद 54 के चार कोनों के भीतर आता है और बिक्री कर से मुक्त है।

अभिनिर्धारित किया गया कि जब भी किसी व्यापार में लगे व्यक्ति पर विधि के अधिकार के बिना कर लगाने की मांग की जाती है, तो उसके मौलिक अधिकारों में से एक का उल्लंघन होता है और वह न्यायालय का द्वार खटखटाने और संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उसकी असाधारण अधिकारिता का आह्वान करने का हकदार है, भले ही उसके पास अपील और पुनरीक्षण के वैकल्पिक उपाय हों, जिनका उसने लाभ नहीं उठाया है।

माननीय न्यायमूर्ति पी. सी. पंडित द्वारा 2 मई, 1969 को इस मामले में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक खंड पीठ को भेजा गया मामला।

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. के. महाजन और माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. डी. कोशल की खंडपीठ ने अंततः दिसंबर, 1969 को मामले का फैसला सुनाया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में अनुरोध किया गया है कि दिनांक 21 नवंबर, 1968 (वार्षिकी "क") के निर्धारण आदेश को उस सीमा तक, जिस तक उसने चिल्का की बिक्री पर विक्रय कर अधिरोपित किया है, निरस्त करते हुए प्रमाण-पत्र, अधिदेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निदेश का रिट जारी किया जाए और प्रत्यर्थियों को निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए ग्राम चिल्का की बिक्री पर याचिकाकर्ता द्वारा संदत्त विक्रय कर की रकम को वापस करने का निर्देश दिया जाए।

याचिकाकर्ता के लिए सिरी चंद गोयल, और सत्य प्रकाश जैन, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए बालवंत सिंह गुप्ता, अधिवक्ता।

निर्णय

कोशल, जे. -हमारे समक्ष याचिकाकर्ता एक साझेदारी है जिसे मैसर्स मामन चंद-कुंदन लाल (इसके बाद फर्म के रूप में संदर्भित किया गया है) के रूप में जाना जाता है, जो हरियाणा राज्य के जींद जिले के नरवाना में कमीशन एजेंट के रूप में व्यवसाय करते हैं और इस तरह हरियाणा विधानमंडल द्वारा संशोधित पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत बिक्री-कर का आकलन किया जाता है। (hereinafter called the Haryana Act). निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए निर्धारण प्राधिकरण, जिसे प्रत्यर्थी सं. 2 याचिका में, फर्म की ओर से ली गई याचिका को खारिज कर दिया गया कि ग्राम चिल्का जो कि विचाराधीन वर्ष के दौरान फर्म द्वारा किए गए लेनदेन द्वारा कवर की गई एक वस्तु थी, आइटम नं. 15, या चारा आइटम नं 54, हरियाणा अधिनियम की अनुसूची बी की, जो बिक्री-कर से छूट प्राप्त वस्तुओं की गणना करती है। अतः निर्धारण प्राधिकरण ने उस वर्ष के दौरान फर्म द्वारा किए गए चने के चिल्के की बिक्री के लेन-देन को अपने सकल कारोबार में शामिल किया और इसे 6 प्रतिशत की दर से बिक्री-कर के अधीन किया। निर्धारण प्राधिकरण का आदेश दिनांक 21 नवंबर, 1968 का है, जिसे इस याचिका में इस प्रार्थना के साथ चुनौती दी गई है कि इसे उस सीमा तक रद्द कर दिया जाए जिस तक वह प्रमाणपत्र के एक रिट द्वारा ग्राम चिल्का की बिक्री पर बिक्री-कर लगाता है और निर्धारण प्राधिकरण और हरियाणा राज्य (प्रत्यर्थी सं. 1) उपर्युक्त वर्ष के संबंध में उक्त बिक्री पर उनके द्वारा लगाए गए कर की राशि को वापस करने का निर्देश दिया जाए। याचिका के समर्थन में निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष उठाई गई दलीलों को दोहराया जाता है और यह आगे कहा जाता है कि किसी भी मामले में चने के संबंध में चने की बिक्री पर निर्धारित प्रतिशत से अधिक कर नहीं लगाया जा सकता है।

(2) उत्तरदाताओं का मामला यह है कि ग्राम चिल्का न तो ग्राम भूसी है जैसा कि मद सं. 15 और न ही वस्तु संख्या के अर्थ के भीतर चारा। 54 ऊपर उल्लिखित है और फर्म द्वारा की गई इसकी बिक्री पर निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से कर लगाया गया था।

(3) मामला मूल रूप से पी. सी. पंडित, जे. के समक्ष निर्णय के लिए रखा गया था, जिनके कहने पर, हालांकि, यह उनके द्वारा तैयार किए गए कानून के निम्नलिखित दो प्रश्नों के महत्व को देखते हुए निपटान के लिए हमारे सामने आया है:

"1. क्या 'ग्राम चिल्का' मद सं. 15 या मद सं। कर-मुक्त वस्तुओं से संबंधित पंजाब सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1948 (1948 का पंजाब अधिनियम 46) की अनुसूची 'ख' का 54?

2. यदि नहीं, तो क्या 'ग्राम चिल्का' पर ली प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है, जो कि प्रासंगिक समय पर खाद्यान्न पर बिक्री कर की दर थी, या 6 प्रतिशत, जो कि खाद्यान्न के अलावा अन्य वस्तुओं पर बिक्री कर की दर थी?

(4) राज्य के विद्वत वकील द्वारा प्रत्यर्थियों की ओर से इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि फर्म ने हरियाणा अधिनियम में प्रदान की गई अपील और पुनरीक्षण के उपायों का लाभ नहीं उठाया है, याचिका जो संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का आह्वान करना चाहती है, उसे अक्षम के रूप में बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। आपत्ति के समर्थन में रिलायंस वेबबिंग एंड बेल्टिंग फैक्ट्री लिमिटेड, दिल्ली बनाम बिक्री कर अधिकारी, राधे मोहन गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य, गुरु नानक आटा और तेल मिल बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य, और सेल कर अधिकारी, जोधपुर और एक अन्य बनाम एम/एस पर रखा गया है। शिव रतन जी. मोहता, इन प्राधिकरणों में कोई संदेह नहीं है कि आम तौर पर एक निर्धारित संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका का सहारा नहीं ले सकता है जब तक कि वह कराधान कानून के तहत उसके लिए उपलब्ध उपायों को समाप्त नहीं कर देता है। हालांकि, यह नियम अपने अनुप्रयोग में सार्वभौमिक नहीं है और अपवादों को स्वीकार करता है जैसा कि बिक्री कर अधिकारी, जोधपुर में उनके लॉर्डशिप

और एक अन्य बनाम एम/एस द्वारा इंगित किया गया था। शिव रतन जी. मोहता निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ: "निर्धारिती की ओर से यह आग्रह किया गया था कि उन्हें अपील दायर करते समय बिक्री कर जमा करना होगा। भले ही ऐसा है, क्या इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मामले में जिसमें निर्धारिती को बिक्री कर जमा करना पड़ता है, वह बिक्री कर अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए उपायों को दरकिनार कर सकता है? निश्चित रूप से नहीं। किसी मामले में अनुच्छेद 226 के अधीन किसी याचिका पर विचार करने के लिए कुछ और होना चाहिए, कुछ ऐसा जो बिक्री कर अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के मूल में जा रहा है, यह दिखाने के लिए कि यह निर्धारिती को अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए उपायों को अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए स्पष्ट न्याय का मामला होगा। लेकिन चूंकि उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने का फैसला किया है, हम इस स्तर पर इस आधार पर याचिका को खारिज करने के इच्छुक नहीं हैं।

(5) यह कि उपर्युक्त सामान्य नियम, अपवादों के अधीन है, सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपति द्वारा हिम्मतलाल-हरिलाल मेहता बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य में स्पष्ट शब्दों में दोहराया गया था, जिसमें यह कहा गया था: "यह स्पष्ट है कि राज्य ने यह इरादा व्यक्त किया था कि वह निश्चित रूप से अपीलार्थी के खिलाफ अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के लिए आगे बढ़ सकता है यदि वह वापसी करने या मांग को पूरा करने में विफल रहा और कानून के अधिकार के बिना ऐसे गंभीर खतरे के परिणामों से बचने के लिए, और; मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, अनिवार्य के एक रिट के माध्यम से राहत स्पष्ट रूप से उचित राहत थी। मोहम्मद में। यासीन बनाम नगर क्षेत्र समिति, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी व्यवसाय पर अनुज्ञप्ति शुल्क न केवल अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति को छीन लेता है, बल्कि उसका व्यवसाय करने के उसके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध के रूप में भी कार्य करता है और इसलिए, यदि अनुज्ञप्ति शुल्क का अधिरोपण विधि के प्राधिकार के बिना है तो इसे अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन के रूप में चुनौती दी जा सकती है, जिसे अनुच्छेद 226 के अधीन प्रमाणपत्र भी दिया जा सकता है। ये टिप्पणियां वर्तमान मामले की परिस्थितियों पर विपरीत रूप से लागू होती हैं। अधिनियम की धारा 2 (छ) का स्पष्टीकरण 2 अधिकारातीत घोषित किए जाने के पश्चात्, मध्य प्रदेश में अपीलार्थी पर विक्रय कर का कोई अधिरोपण विधि के प्राधिकार के बिना है और यह कि राज्य द्वारा आक्षेपित अधिनियम के बलपूर्वक तंत्र का उपयोग करके अपीलार्थी से उसे प्राप्त करने के लिए इतना खतरा होना अनुच्छेद 19 (1) (छ) के अधीन उसके मौलिक अधिकार का पर्याप्त उल्लंघन है और यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन राहत का हकदार था। यह तर्क कि क्योंकि आक्षेपित अधिनियम के तहत एक उपाय अपीलार्थी के लिए उपलब्ध था, यह अनुच्छेद 226 के तहत राहत के लिए वंचित था, इस न्यायालय के निर्णय से नकार दिया गया है बॉम्बे राज्य बनाम यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड, ऊपर निर्दिष्ट। वहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह सिद्धांत कि पर्याप्त वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर न्यायालय विशेषाधिकार रिट जारी नहीं करेगा, उस स्थिति में लागू नहीं हो सकता था जब कोई पक्षकार इस आरोप के साथ न्यायालय में आया था कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था और उसने अनुच्छेद 226 के तहत राहत मांगी थी। इसके अलावा, अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया उपाय एक कठिन और बोझिल प्रकृति का है। इससे पहले कि अपीलार्थी इसका लाभ उठा सके, उसे कर की पूरी राशि जमा करनी होगी। इस तरह के प्रावधान को शायद ही एक पर्याप्त वैकल्पिक उपाय के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

(7) कैलाश नाथ और एक अन्य बनाम U.P. राज्य और अन्य में, मामले को इस प्रकार निपटाया गया था-"राज्य सरकार की ओर से एक आपत्ति ली गई है कि एक अवैध कर लगाने से नागरिक को अनुच्छेद 32 का आह्वान करने का अधिकार नहीं मिलेगा; लेकिन उसे सामान्य कानून के तहत उपलब्ध उपचारों का सहारा लेना चाहिए या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आगे बढ़ना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कर के भुगतान से छूट का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता है जो अनुच्छेद 32 के दायरे में आता है। इस तर्क का बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर कोई बल नहीं है, जहां बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947 से संबंधित एक पूर्ण पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:-"हम उपरोक्त निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं। उस निष्कर्ष पर पहुँचने में ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि अपीलार्थी कंपनी का मुख्य तर्क, जैसा कि उसकी याचिका में दिया गया है, यह है

कि अधिनियम, जहाँ तक वह अंतर-राज्यीय बिक्री या वस्तुओं की खरीद के संबंध में एक अनिवासी विक्रेता पर कर लगाने का तात्पर्य रखता है, संविधान के अधिकार से बाहर है और पूरी तरह से अवैध है। आक्षेपित अधिनियम में विभिन्न प्रावधान हैं जो शर्तों का पालन करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, अर्थात्, केवल कुछ उदाहरण देने के लिए, डीलरों का अनिवार्य पंजीकरण (धारा 10) रिटर्न दाखिल करना (धारा 12) उपस्थिति और रिटर्न के समर्थन में साक्ष्य का उत्पादन (धारा 13) लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों का उत्पादन, निरीक्षण और जब्ती और परिसर की तलाशी। (section 17). धारा 26 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करती है ये और अधिनियम के अन्य समान प्रावधान निस्संदेह व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध का गठन करते हैं जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19। (1) (g) द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को दी गई है। यदि, जैसा कि प्रतिवाद किया गया है, अधिनियम संविधान के अधिकार से बाहर है और फलस्वरूप इन कठिन शर्तों को शून्य करता है, तो उस अनुच्छेद के खंड (6) के अर्थ के भीतर उचित प्रतिबंधों के रूप में कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय ने मोहम्मद यासीन बनाम नगर क्षेत्र समिति, जलालाबाद के मामले में अभिनिर्धारित किया था। यही दृष्टिकोण द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम द यूनाइटेड मोटर (इंडिया) लिमिटेड में भी व्यक्त किया गया था, और फिर हाल ही में हिम्मतलाई-हरिलाल मेहता बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, (5)

ऊपर उल्लिखित मामलों के अलावा, इस विषय से निपटने वाला एक और अधिक हालिया प्राधिकरण है, अर्थात्, बिडी सप्लाई कंपनी बनाम भारत संघ और अन्य। इसलिए हमें यह पता लगाना है कि क्या वर्ष 1953-54 के दौरान विक्रेताओं को बेचे गए कपड़े की मात्रा के संबंध में बिक्री कर प्राधिकरणों द्वारा छूट खंड पर दी गई व्याख्या कानूनी रूप से सही है।

(7) और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक करों के सहायक आयुक्त और एक अन्य मामले में, उनके लॉर्डशिप्स ने कहा: "संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय से स्पष्टीकरण का विषय रहा है। यह असाधारण है और इसका कम उपयोग किया जाना बिना किसी बचत के चला जाता है। बहुत व्यापक शर्तों के बावजूद जिसमें यह अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, उच्च न्यायालयों ने इस शक्ति पर कुछ सीमाओं को उचित रूप से मान्यता दी है। अधिकार क्षेत्र अपीलीय नहीं है और यह स्पष्ट है कि यह कानून में सामान्य उपचारों का विकल्प नहीं हो सकता है। न ही इसका अभ्यास वांछनीय है यदि तथ्यों को साक्ष्य पर पाया जाना है। इसलिए, उच्च न्यायालय पक्षकार को साधारण कानून के तहत उपलब्ध उपचारों का सहारा लेने के लिए व्यथित करता है यदि वे समान रूप से प्रभावी हैं और ऐसे उपचारों को पारित करने में सक्षम बनाने के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने से इनकार करते हैं। इनके कुछ अपवाद भी हैं। ऐसा ही एक अपवाद है जहां अवैध कानून के तहत या कानून की मंजूरी के बिना मनमाने ढंग से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय किसी पक्षकार की कठिनाई से बचने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है जो अपरिहार्य होगा यदि अनुच्छेद 226 द्वारा परिकल्पित त्वरित और अधिक प्रभावी उपचार को लागू करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हमारे निर्णय में वर्तमान उस असाधारण स्थिति का एक उदाहरण है जिस पर ऊपर विचार किया गया है, जैसे हिम्मतलाल बनाम M.P. का राज्य, एक और उदाहरण था जो इस न्यायालय के समक्ष आया था।

(8) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब भी व्यापार में लगे किसी व्यक्ति पर विधि के अधिकार के बिना कर लगाने की मांग की जाती है, तो उसके मौलिक अधिकारों में से एक का उल्लंघन होता है और वह इस न्यायालय के द्वार पर दस्तक देने और संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इसकी असाधारण अधिकारिता का आह्वान करने का हकदार है। पंजाब के जिन तीन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से सभी एकल पीठ के निर्णयों को शामिल करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे कानून को सही ढंग से निर्धारित करते हैं, जहां तक कि यह सर्वोच्च न्यायालय के उनके प्रभुओं के आदेश के खिलाफ जाता है, जिसके मद्देनजर आपत्ति को आधारहीन माना जाना चाहिए और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

(9) हरियाणा अधिनियम की धारा 6 इस प्रकार है: "अनुसूची बी के पहले कॉलम में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर कोई कर देय नहीं होगा, बशर्ते कि उसके दूसरे कॉलम में संबंधित प्रविष्टि में दी गई शर्त और अपवाद, यदि कोई हों, और कोई भी विक्रेता उन वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर नहीं लेगा जिन्हें इस धारा के तहत समय-समय पर कर-मुक्त घोषित किया जाता है।

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने इरादे की कम से कम तीस दिनों की सूचना देने के बाद, इसी तरह की अधिसूचना द्वारा अनुसूची बी से जोड़ या हटा सकती है और उसके बाद अनुसूची बी को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।

(10) जैसा कि पहले ही कहा गया है; हरियाणा अधिनियम की अनुसूची ख उन वस्तुओं की गणना करती है जिन्हें धारा 6 के तहत छूट दी गई है और जिनकी बिक्री पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जाता है। आइटम संख्या। अनुसूची के 15 और 54 को संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

"15. सभी खाद्यान्नों की भूसी "।

(54) हर प्रकार का चारा (सूखा या हरा)।

हरियाणा अधिनियम में "भूसी" और "चारा" शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए उनका कोई विशेष अर्थ नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने रामावतार बनाम सहायक विक्रय कर अधिकारी (12) में इस बात पर जोर दिया है कि कर कानूनों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ किसी तकनीकी अर्थ में नहीं बल्कि सामान्य बोलचाल में समझा जाना चाहिए और यदि कोई शब्द या शब्द रोजमर्रा के उपयोग का है। इसका अर्थ इसके लोकप्रिय अर्थ में लगाया जाना चाहिए, अर्थात्, "वह अर्थ जो लोग उस विषय-वस्तु से परिचित हैं जिसके साथ कानून काम कर रहा है, वह इसके लिए जिम्मेदार होगा।" इस प्रकार यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या चना चिल्का जो कि चना के बीज से निकाली गई भूरे रंग की त्वचा के अलावा और कुछ नहीं है, लोकप्रिय अर्थ के भीतर भूसी है। इस संबंध में भारत सरकार के प्रकाशन "भारत में कृषि विपणन: भारत में चने के विपणन पर रिपोर्ट" में प्रकाशित अध्याय VI के दो भागों का उपयोगी संदर्भ दिया जा सकता है। उन भागों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"अध्याय VI। चना उत्पादों का प्रसंस्करण और वितरण। A. प्रोसेसिंग।

जैसा कि पिछले अध्याय में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, चने का सेवन दाल, बैसिन, चना आटा, कुचले हुए या पूरे चने को उबाले या सूखे के रूप में किया जाता है। दाल के निर्माण में, चने को चक्कियों के माध्यम से अनाज को विभाजित करने और भूसी और गुठली को अलग करने के लिए पारित किया जाता है, जबकि बैसिन और चना आटा क्रमशः दाल और चना को पीसकर तैयार किया जाता है।

* * * * *

(घ) उप-उत्पाद। चूनी और भूसी दाल उत्पादन के उप-उत्पाद हैं। चूनी और भूसी की उपज प्रति 100 मण

ग्राम की संख्या स्थान-स्थान पर भिन्न होती है जैसा कि पृष्ठ 45 पर दिखाया गया है। चूनी दाल और "भूसी" के छोटे दानों का मिश्रण है।

इन निष्कर्षों में कोई संदेह नहीं है कि जहां तक चने की भूसी के रूप में जानी जाने वाली वस्तु का संबंध है, यह वाणिज्यिक दुनिया में चने के बीज की भूरे रंग की त्वचा के रूप में समझा जाता है, न कि चने की भूसी जो कटाई की प्रक्रिया के दौरान पूरे चने से अलग होती है। इसलिए, राज्य के लिए विद्वान वकील द्वारा इसके विपरीत तर्क अस्वीकार्य है।

(11) "भूसी" शब्द का शब्दकोश अर्थ एक ही निष्कर्ष की ओर ले जाता है, हालांकि एक अलग तरीके से। वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी का अर्थ है "भूसी": "एक गुठली या बीज का बाहरी आवरण विशेष रूप से जब सूखा और झिल्लीदार होता है: अनाज हल से भूसी, पीओडी: मकई के कान को घेरने वाले पत्तों में से एक:

(12) वेबस्टर के अनुसार, इसलिए चने की भूसी न केवल चने का छिलका बल्कि चने की भूसी के साथ-साथ चने की फली को भी बांधती है। इसलिए, शब्द का शब्दकोश अर्थ चने की भूसी के रूप में जानी जाने वाली वस्तु से जुड़े लोकप्रिय अर्थ से अधिक व्यापक है। और यदि पूर्व को मद सं. के प्रयोजनों के लिए अपनाया जाना था। 15, यह सब कहा जा सकता है कि न केवल चना छिलका बल्कि चना भूसी भी उस वस्तु द्वारा कवर किया जाएगा ताकि चना चिल्का उस मामले में बिक्री कर से छूट के लिए उत्तरदायी हो।

(13) वह ग्राम चिल्का भी परिच्छेद संख्या के अंतर्गत आएगा। 54 बिना किसी संदेह के स्वीकार करते हैं। वेबस्टर "चारा" शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है:

* * *: घरेलू जानवरों को खिलाया जाने वाला कुछ: मवेशियों, घोड़ों और भेड़ों के लिए मोटा भोजन (जैसे घास, सब्जियां; मकई का चारा)* * * "

राज्य का विद्वान वकील इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता है कि यह परिभाषा मद सं. 54. हालांकि, वे तर्क देते हैं, और हमारी राय में, पूरी तरह से बिना किसी औचित्य के, कि चना चिल्का का उपयोग "मानव उपभोग के भोजन के रूप में भी किया जा सकता है"। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चने का उपयोग मनुष्यों के उपभोग के लिए भोजन के रूप में किया जाता है और उस रूप में चने का छिलका इसका एक हिस्सा है, लेकिन हम इसे एक बेतुका दावा मानते हैं कि अनाज के चिल्का का उपयोग दुनिया के किसी भी हिस्से में मनुष्यों के भोजन के रूप में किया जाता है। राज्य के विद्वान वकील को जब ग्राम चिल्का के उपयोग का उदाहरण देने के लिए कहा गया, तो वे ऐसा करने में असमर्थ थे। हालांकि, अगर यह अन्यथा भी था, तो यह नहीं कहा जा सकता था कि चना चिल्का का मुख्य उपयोग मवेशियों के भोजन के रूप में और इसलिए चारे के रूप में किया जाता है। ग्राम चिल्का उस मामले में भी, इसलिए, आइटम नंबर के चार कोनों के भीतर आता है। 54. सवाल नं. इस प्रकार संदर्भ क्रम में पंडित, जे. द्वारा प्रस्तुत 1 का उत्तर हां में दिया जाना चाहिए।

(14) पंडित, जे. द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पर अभी-अभी आए निष्कर्ष को देखते हुए, निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि, यह कहा जा सकता है कि हमारी राय में चना छिलका 6 प्रतिशत की दर से बिक्री कर के लिए उत्तरदायी होगा, न कि खाद्यान्न को कवर करने वाली बिक्री को नियंत्रित करने वाली दर मात्र 1 प्रतिशत) हालांकि, फर्म के विद्वान वकील ने अधिसूचना संख्या 12 के परंतुक के आधार पर इसके विपरीत तर्क दिया है। S.O. 175/पीए, 46/48/एस-5/66 दिनांक 30 जून, 1966 को पूर्ववर्ती पंजाब सरकार द्वारा पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

"इस विषय पर सभी पिछली अधिसूचनाओं के स्थान पर और पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल ने यह निर्देश दिया है कि 1 जुलाई, 1966 से एक व्यापारी के कर योग्य कारोबार पर एक रुपये में छह पैसे की दर से कर लगाया जाएगा:

बशर्ते कि:

(12) गेहूं और उसके आटे पर कर की दर, जिसमें मैदा और सुजी, मक्का और उसका आटा, बाजरा और उसका आटा, जौ और उसका आटा, चना, चने का आटा, चुरी (छड़ी) मूंग और दाल मूंग, मक्के और दाल की चटनी, शहतूत और दाल की चटनी, मसूर और दाल मसूर, मलका मसूर और दाल मलका मसूर, अरहर और दाल अरहर, ज्वार और उसका आटा, ग्वारा और उसका आटा, सूखी मटर, उसकी दाल और आटा एक रुपये में डेढ़ पैसे होंगे।

(15) फर्म के लिए परंतुक (12) में आने वाले "चना, दाल चना, चना आटा, चूड़ी (छड़ी)" शब्दों पर जोर दिया गया है और यह आग्रह किया गया है कि चूड़ी में चना चिल्का शामिल होगा। भले ही ऐसा चिल्का चूड़ी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह चूड़ी के समान नहीं है और इसलिए इसे परंतुक के अंतर्गत नहीं कहा जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रावधान में दाल चना और चने के आटे का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, भले ही वे पूरे चने से प्राप्त होते हैं जिसका उसमें भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विहश v का अर्थ है वस्तुओं को उन रूपों में शामिल करना जिन्हें उनके नाम इंगित करते हैं, न कि उन वस्तुओं के घटकों को कम करना। इसलिए, चूड़ी का अर्थ होगा चूड़ी, न कि केवल इसका एक घटक, अर्थात् चना चिल्का।

(16) फर्म की ओर से यह स्वीकार किया जाता है कि यदि ग्राम चिल्का वस्तुओं की संख्या के दायरे में नहीं आता है। 15 और 54 और ऊपर उल्लिखित परंतुक (12) के अनुसार, यह एक रुपये में 6 पैसे की दर से बिक्री कर के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए हम प्रश्न संख्या का उत्तर देंगे। 2 पंडित, जे. द्वारा यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया कि यदि ग्राम चिल्का दो वस्तुओं में से किसी एक द्वारा कवर नहीं किया जाता है, तो यह 6 प्रतिशत की दर से बिक्री कर के लिए उत्तरदायी होगा, यानी, खाद्यान्न के अलावा अन्य वस्तुओं पर लागू दर पर।

(11) प्रश्न संख्या के हमारे उत्तर को देखते हुए। 1 पी. सी. पंडित जे. द्वारा प्रस्तुत याचिका सफल होती है। आक्षेपित आदेश को इस हद तक निरस्त कर दिया जाता है कि वह ग्राम चिल्का पर कर लगाता है और प्रत्यर्थियों को निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए ऐसी बिक्री पर फर्म से वसूले गए बिक्री कर की राशि, यदि कोई हो, को वापस करने का निर्देश दिया जाता है। फर्म के पास याचिका का खर्च भी होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)